तमिलनाडु की चीनी मिलों ने कर्ज चुकाने के लिए मांगी बैंकों से मोहलत

क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं होने से राज्य में चीनी की उत्पादन लागत ₹43 प्रति किलो है, जो देश में सबसे ज्यादा है

[भरनी वैतीश्वरन | चेन्नई]

कर्ज के बढ़ते बोझ से बेहाल तमिलनाडु की कुछ चीनी मिलों की मदद के लिए बैंक रास्ते तलाश रहे हैं। खराब मॉनसून और चीनी की कम कीमतों के कारण इनके मुनाफे पर बुरा असर पड़ा है और ये कर्ज नहीं चुका पा रही हैं। राज्य की पांच चीनी मिलें बैंकों के लिए नॉन-परफॉर्मिंग एसेट बन गई हैं। इन मिलों ने बैंकों से कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाने की मांग की है। तमिलनाडु में गन्ने से चीनी की रिकवरी कम रहती है और राज्य में पिछले कुछ वर्षों में बारिश भी कम हुई है।

एक चीनी मिल के अधिकारी ने बताया कि राज्य की मिलों को एक किलो चीनी पर 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं होने की वजह से यहां चीनी की प्रॉडक्शन कॉस्ट 43 रुपये किलो है, जो देश में सबसे अधिक है। चीनी मिल मालिकों ने बैंकों से निवेदन किया है कि वे अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए कानून का इस्तेमाल न करें। साउथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पलानी जी पेरिसामी ने ईटी को बताया कि तमिलनाडु में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चीनी मिलें महत्वपूर्ण हैं।

सितंबर में खत्म हुए 2018-19 के शुगर ईयर में तमिलनाडु की चीनी मिलों ने 9 लाख टन से अधिक उत्पादन किया, जो 2011-12 में 24 लाख टन था

पेरिसामी का PGP ग्रुप धरानी शुगर्स चलाता है। धरानी शुगर्स ने हाल ही स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि उसने अपने बैंकों को एकमुश्त सेटलमेंट का प्रपोजल दिया है। इनमें से एक बैंक ने अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में याचिका दायर की है। तमिलनाडु में बैंकों की एक कमेटी ने चीनी मिलों की लोन की समस्या के समाधान पर विचार करने के लिए बैठकें की हैं। सितंबर के अंत में बैंकर्स, चीनी मिलों के सीनियर एग्जिक्यूटिव्स, किसानों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में मिलों की परेशानियों, किसानों की बकाया रकम और लोन चुकाने में मुश्किल जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तमिलनाडु की चीनी मिलें पिछले कुछ वर्षों से कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। आने वाले शुगर ईयर में भी यह स्थिति बरकरार रह सकती है। सितंबर में खत्म हुए 2018-19 के शुगर ईयर में तमिलनाडु की चीनी मिलों ने 9 लाख टन से अधिक उत्पादन किया, जो 2011-12 में 24 लाख टन से काफी कम है। चीनी मिलों के सामने लोन चुकाने के संकट से किसान भी चिंतित हैं। की मांग की है।

Economic Times
16/10/19